

छत्तीसगढ़ में पिछले 10 वर्षों में कृषि योजनाओं का किसानों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति पर प्रभाव : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

टिकेश्वरी जायसवाल शोधार्थी-(समाजशास्त्र विभाग)

रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी, रायपुर, छत्तीसगढ़

E-mail: tiyadadsena@gmail.com

डॉ. अर्चना आर. तुपट

असिस्टेंट प्रोफेसर (समाजशास्त्र विभाग)

श्री रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी, रायपुर, छत्तीसगढ़

E-mail: archanatulpat2784@gmail.com

सारांश

प्रस्तुत शोध-पत्र छत्तीसगढ़ राज्य में विगत दस वर्षों के दौरान संचालित विभिन्न कृषि योजनाओं का किसानों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति पर पड़े प्रभाव का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से विश्लेषण करता है। छत्तीसगढ़ एक कृषि प्रधान राज्य है, जहाँ अधिकांश जनसंख्या कृषि एवं उससे संबंधित गतिविधियों पर निर्भर है। ऐसे में किसानों के विकास हेतु केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा अनेक योजनाएँ लागू की गई हैं, जिनका उद्देश्य कृषि उत्पादन में वृद्धि, किसानों की आय में सुधार, सामाजिक सुरक्षा तथा जीवन-स्तर को ऊँचा उठाना रहा है।

इस अध्ययन में प्रमुख योजनाओं जैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं धान खरीदी व्यवस्था, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) एवं राज्य स्तरीय किसान कल्याण योजनाओं का समग्र अध्ययन किया गया है। शोध के लिए प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के आँकड़ों का उपयोग किया गया है। प्राथमिक आँकड़े चयनित जिलों के किसानों से साक्षात्कार एवं प्रश्नावली के माध्यम से एकत्र किए गए, जबकि द्वितीयक आँकड़े सरकारी रिपोर्टों, कृषि विभाग के अभिलेखों एवं पूर्ववर्ती शोध अध्ययनों से प्राप्त किए गए हैं।

अध्ययन के निष्कर्ष दर्शाते हैं कि पिछले दस वर्षों में कृषि योजनाओं के प्रभाव से किसानों की आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, कृषि जोखिमों में कमी तथा आय के स्रोतों में विविधता देखी गई है। सामाजिक स्तर पर किसानों की शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, सामाजिक सुरक्षा एवं संस्थागत सहभागिता में सुधार हुआ है, जिससे उनके सामाजिक दर्जे एवं आत्मसम्मान में वृद्धि हुई है। तथापि, योजनाओं के क्रियान्वयन में क्षेत्रीय असमानता, सीमांत किसानों की सीमित पहुँच, जागरूकता की कमी एवं प्रशासनिक जटिलताएँ जैसी समस्याएँ अभी भी विद्यमान हैं। निष्कर्षतः, कृषि योजनाएँ छत्तीसगढ़ के किसानों के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण का एक प्रभावी साधन सिद्ध हुई हैं, परंतु इनके प्रभाव को अधिक समावेशी एवं स्थायी बनाने हेतु नीतिगत सुधार एवं सुदृढ़ क्रियान्वयन की आवश्यकता है।

मुख्य शब्द : कृषि कल्याण योजनाएँ, योजनोका सामाजिक और आर्थिक प्रभाव, ग्रामीण विकास, ग्रामीण आजीविका, सरकारी नीतियाँ, किसान सशक्तिकरण

1. परिचय

छत्तीसगढ़ राज्य की अर्थव्यवस्था का आधार कृषि है। राज्य की लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। विगत दस वर्षों में कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ करने हेतु अनेक योजनाएँ लागू की गई हैं, जिनका उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि, कृषि जोखिम को कम करना एवं ग्रामीण समाज के समग्र विकास को सुनिश्चित करना है। इन योजनाओं के सामाजिक एवं आर्थिक प्रभावों का समाजशास्त्रीय अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। भारतीय समाज परंपरागत रूप से पितृसत्तात्मक रहा है, जहाँ पारिवारिक, आर्थिक एवं सामाजिक निर्णयों पर पुरुषों का प्रभुत्व रहा है। किंतु शिक्षा, शहरीकरण, आर्थिक विकास तथा महिलाओं की बढ़ती रोजगार भागीदारी ने पारिवारिक संरचना और लैंगिक भूमिकाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं। (Panda Uttam Kumar 2019) छत्तीसगढ़ जैसे कृषि प्रधान राज्यों में पिछले दस वर्षों में लागू की गई विभिन्न कृषि योजनाओं ने किसानों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय परिवर्तन लाने का प्रयास किया है। जहाँ सोशल मीडिया और सोशल नेटवर्किंग साइट्स उनके जीवन में सूचना तक त्वरित पहुँच, सामाजिक संपर्क और पहचान निर्माण के नए आयाम प्रस्तुत करती हैं, समाजशास्त्रीय अध्ययन यह समझने में सहायक है कि आधुनिक संचार माध्यम और विकासात्मक योजनाएँ किस प्रकार भारतीय समाज में सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन की दिशा को निर्धारित कर रही हैं। छत्तीसगढ़ में पिछले दस वर्षों में लागू कृषि योजनाओं ने किसानों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में परिवर्तन लाने का प्रयास किया है। दोनों ही संदर्भ यह दर्शाते हैं कि तकनीकी विकास और नीतिगत हस्तक्षेप समाज के विभिन्न वर्गों की स्थिति-गतिशीलता को प्रभावित करते हैं। यह अध्ययन इन प्रभावों का समाजशास्त्रीय विश्लेषण प्रस्तुत करता है। (तुपट, अर्चना आर. एंड महापात्र मनीषा (2019))

किसान क्रेडिट कार्ड (KCC)

KCC योजना कृषि क्षेत्र के किसानों को फसल उगाने और खेती-बाड़ी संबंधी खर्चों के लिए समय पर और कम-ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराती है। इसका उद्देश्य किसानों को महँगे निजी उधारदाताओं से बचाना और कृषि-उत्पादन लागत को नियंत्रित करना है। [mint](#)

2025-26 के बजट में KCC की लोन लिमिट को ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख कर दिया गया है ताकि किसानों को अधिक फंड तक पहुँच मिल सके। [The Times of India](#)

कृषक उन्नति योजना

- कृषक उन्नति योजना छत्तीसगढ़ सरकार की एक प्रमुख कृषि सहायता योजना है, जिसका उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना, खेती का खर्च कम करना और उन्हें समर्थन मूल्य-संबंधित अतिरिक्त भुगतान प्रदान करना है। [Krishak Jagat \(कृषक जगत\)+1](#)

- खासकर इसे धान किसानों के लिए मूल्य अंतर भुगतान (input assistance/bonus) के रूप में शुरू किया गया, ताकि वे MSP के अलावा अतिरिक्त राशि सीधे उनके बैंक खातों में प्राप्त कर सकें। <https://mpcg.ndtv.in/>

- बाद में इसे व्यापक बनाकर मक्का, दलहन, तिलहन जैसी अन्य फसल उत्पादकों तक भी लाभ पहुंचाया गया। [Krishak Jagat \(कृषक जगत\)+1](#)

जैविक खेती मिशन

जैविक खेती मिशन का उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के स्थान पर प्राकृतिक व जैविक तरीकों को अपनाकर खेती को सतत, सुरक्षित और लाभकारी बनाना है। इससे मिट्टी की उर्वरता, पर्यावरण संरक्षण और किसानों की आय में सुधार होता है।

PM-Kisan योजना

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) एक प्रत्यक्ष नकद सहायता योजना है जो भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है।

भूमि-धारक किसान परिवारों को हर वर्ष ₹6,000 की सहायता (3 किस्तों में ₹2,000-₹2,000) सीधे उनके बैंक खाते में दी जाती है। [Drishti IAS](#)

छत्तीसगढ़ में भी लाखों किसान इस योजना के तहत लाभान्वित हुए हैं – उदाहरण के लिए 19वीं किस्त में लगभग 25.95 लाख किसानों को लगभग ₹599.38 करोड़ मिले। [Amar Ujala](#)

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) प्राकृतिक आपदाओं (सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, कीट-प्रकोप आदि) से होने वाली फसल हानि का कवरेज प्रदान कर किसानों को आर्थिक सुरक्षा देना है। इसमें प्राकृतिक जोखिम, कीट तथा रोग क्षति के कारण फसल में नुकसान पर किसानों को भरपाई दी जाती है ताकि जोखिम-दृष्टि से आय सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। [IBC24 News](#)

1. सरकारी कृषि खर्च और निवेश (Economic Inputs)

बजट आवंटन वृद्धि (2013-14 → 2024-25):

- कृषि और किसान कल्याण विभाग के बजट में लगभग 5 गुना वृद्धि हुई है: ₹27,663 करोड़ → ₹1,37,664 करोड़। [The Times of India](#)

कृषि पर खर्च लगभग 6 गुना बढ़ा:

- केंद्र सरकार का कृषि पर खर्च पिछली 10-11 वर्षों में 6 गुना तक बढ़ा। [Money control Hindi](#)

2. किसान आय सहायता और क्रेडिट (Income Support & Credit)

PM-KISAN (2019 से):

- अब तक ₹3.7 लाख करोड़ से अधिक सीधे 1.1 करोड़ से ज़्यादा किसानों को दिया गया। [The Economic Times](#)

किसान क्रेडिट कार्ड (KCC):

- लगभग ₹10 लाख करोड़ का कर्ज 7.71 करोड़ किसानों को मिला। [The Economic Times](#)

3. MSP और बाजार समर्थन (Price Support)

Minimum Support Price (MSP) में बड़ा इज़ाफ़ा:

- गेहूं MSP ₹1400 → ₹2425 प्रति क्विंटल
- धान MSP ₹1310 → ₹2369 प्रति क्विंटल (2013-14 → 2024-25) [The Economic Times](#)+1

MSP आधारित खरीदी:

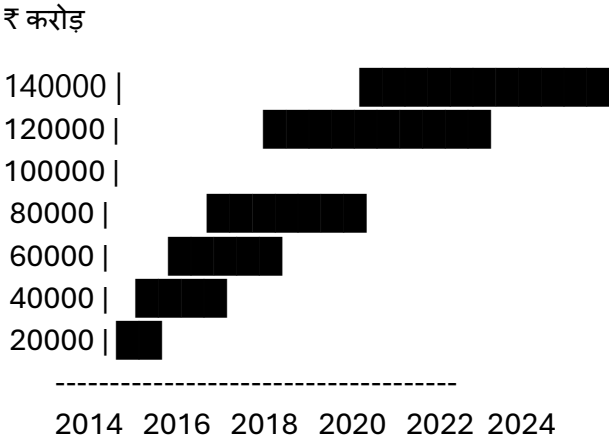
- खरीफ फसल खरीदी में वृद्धि: 787.1 मिलियन टन (2015-25) vs 467.9 मिलियन टन (2004-14) [The Economic Times](#)

4. उत्पादन और कृषि वृद्धि (Production & Growth)

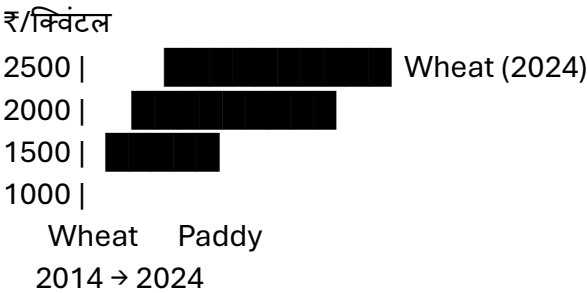
खाद्य अनाज उत्पादन:

- 2014-15 → ~347.44 मिलियन टन तक उत्पादन वृद्धि। [The Times of India](#)

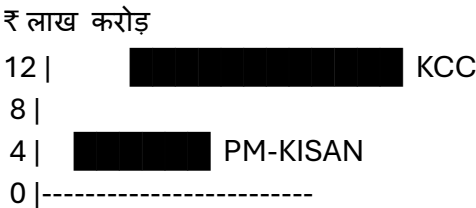
डायग्राम 1. कृषि बजट वृद्धि



डायग्राम 2: MSP तुलना (Wheat & Paddy)



डायग्राम 3: किसान आर्थिक सहायता

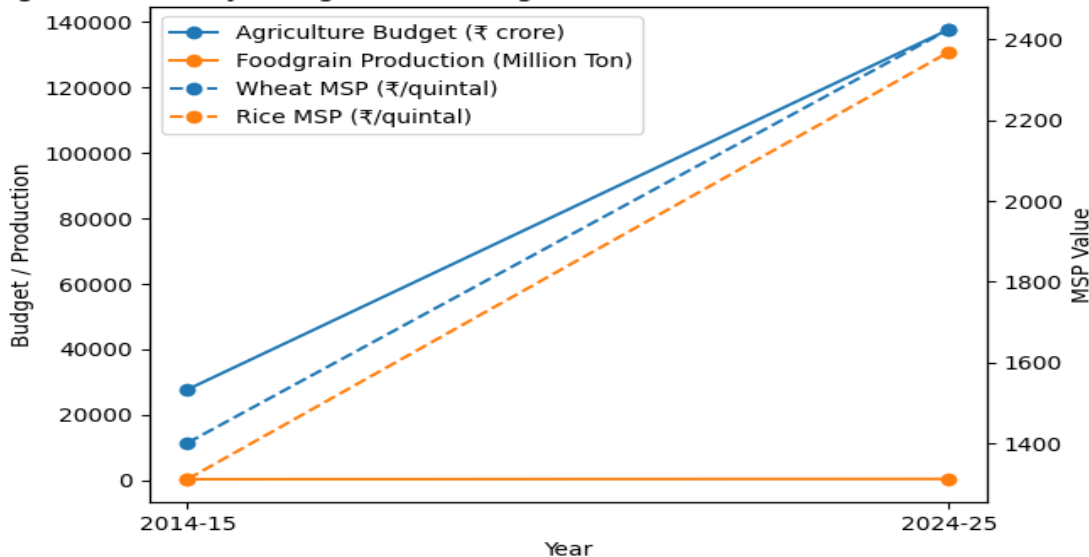


तालिका क्रमांक 1. सालाना कृषि वृद्धि दर

- औसत ~5% (FY17-23) | [DD News](#)

मापदंड (2014-15 vs 2024-25)	2014-15	2024-25	बदलाव
कृषि बजट आवंटन (₹ करोड़)	27,663	1,37,664	~5× बढ़ा
गेहूं MSP (₹/क्विंटल)	1,400	2,425	~73% बढ़ा
धान MSP (₹/क्विंटल)	1,310	2,369	~81% बढ़ा
PM-KISAN वितरण (₹ लाख करोड़)	—	3.7	बड़ा लाभ
KCC क्रेडिट (₹ लाख करोड़)	—	10	बड़ा लाभ
खाद्य अनाज उत्पादन (मिलियन टन)	265	~347	~31% वृद्धि

Merged Trend Analysis: Agriculture Budget, Production and MSP (2014-15 vs 2024-25)



आधुनिक भारतीय समाज तीव्र सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक परिवर्तनों के दौर से गुजर रहा है, जहाँ एक ओर डिजिटल प्रौद्योगिकी और सोशल नेटवर्किंग प्लेटफार्म लोगो के सांस्कृतिक दृष्टिकोण, सामाजिक व्यवहार और पहचान निर्माण को प्रभावित कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कृषि प्रधान राज्यों जैसे छत्तीसगढ़ में पिछले दस वर्षों में लागू की गई विभिन्न कृषि योजनाएँ किसानों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में परिवर्तन लाने का प्रयास कर रही हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट्स ने, कृषि योजनाओं ने किसानों के जीवन स्तर, आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक सम्मान को सुदृढ़ करने की दिशा में योगदान दिया है। दोनों ही प्रक्रियाएँ यह दर्शाती हैं कि तकनीकी और नीतिगत हस्तक्षेप समाज के विभिन्न वर्गों में सांस्कृतिक एवं संरचनात्मक परिवर्तन को गति प्रदान करते हैं।

अतः यह स्पष्ट होता है कि सोशल नेटवर्किंग के सांस्कृतिक प्रभाव और कृषि योजनाओं के सामाजिक-आर्थिक परिणाम, दोनों ही भारतीय समाज में परिवर्तन की प्रक्रिया को विभिन्न स्तरों पर प्रभावित कर रहे हैं। युवाओं और किसानों के अनुभव यह दर्शाते हैं कि तकनीकी नवाचार और विकासात्मक नीतियाँ, यदि समावेशी और संतुलित रूप से लागू की जाएँ, तो सामाजिक विकास और सांस्कृतिक सुदृढ़ीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।

(पंडा, उत्तम कुमार, तुपट, अर्चना रामभाऊ (2023).)

पूर्वअध्यायनों का पुनरावलोकन

1. मलिक, सोनिया एट अल, (2022) ने अपने अध्ययन भारत में KCC योजना की प्रगति पर मूल्यांकन में भारत में यह शोध पत्र कृषि क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करने के संदर्भ में हुई प्रगति का मूल्यांकन करता है। वर्ष 1998 में आर. वी. गुप्ता समिति की सिफारिशों के आधार पर प्रारंभ की गई किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना का उद्देश्य किसानों को समय पर एवं सुलभ ऋण सुविधा उपलब्ध कराना था। इस अध्ययन की अवधि 1999-00 से 2018-19 तक की रही, जिसमें वर्षवार, एजेंसीवार तथा क्षेत्रवार केसीसी की प्रगति का विश्लेषण किया गया। शोध निष्कर्षों से यह स्पष्ट हुआ कि इस अवधि के दौरान केसीसी की संख्या तथा स्वीकृत ऋण राशि—दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। विशेष रूप से यह भी पाया गया कि योजना के कार्यान्वयन में वाणिज्यिक बैंकों का प्रदर्शन ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों की तुलना में बेहतर रहा।
2. कुमार, आर. (2020), के इस अध्ययन छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) का प्रभाव. के अनुसार छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के प्रभाव का मूल्यांकन किया गया। चार गाँवों से 120 किसानों (बीमा लाभार्थी और गैर-लाभार्थी) का चयन कर

धान फसल के आधार पर अध्ययन किया गया। परिणामों से पता चला कि फसल बीमा लेने वाले किसानों की शिक्षा, भूमि आकार, इनपुट उपयोग, उत्पादन तथा आय गैर-बीमित किसानों की तुलना में अधिक थी। बीमित किसानों की प्रति हेक्टेयर लागत ₹56,119.82 और उत्पादन से औसत आय ₹64,242.68 रही, जबकि गैर-बीमित किसानों में यह क्रमशः ₹53,129 और ₹63,076 थी। रायपुर ज़िले में PMFBY की प्रगति भी बेहतर रही। खरीफ 2016 से 2018 के बीच बीमित किसानों की संख्या 5.42% बढ़ी, जबकि बीमित क्षेत्रफल में 3.3% की कमी आई। बीमित राशि में 28% की वृद्धि हुई तथा दावों की संख्या और भुगतान में क्रमशः 1340% और 1944% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। अधिकांश किसानों ने योजना को उत्पादन हानि से सुरक्षा देने वाली बताया, हालांकि मुआवज़े को अपर्याप्त माना। कुल मिलाकर अध्ययन दर्शाता है कि PMFBY अपनाने वाले किसानों को बेहतर उत्पादन और अधिक आय प्राप्त हुई, जिससे यह योजना किसानों के लिए लाभकारी सिद्ध होती है।

3. यादव, पी.के. (2020) द्वारा किए गए अध्ययन केवीके द्वारा किसान मोबाइल सलाहकार सेवाओं के माध्यम से कृषि में आईसीटी पहल पर एक अध्ययन के अनुसार बिलासपुर जिले के चार चयनित ब्लॉकों में 120 किसानों पर किया गया, जहाँ अधिकांश उत्तरदाता 36–50 वर्ष आयु वर्ग, हायर सेकेंडरी शिक्षित और मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर पाए गए। उनकी आय का प्रमुख स्रोत खेती था और अधिकतर किसान 1.1–2 हेक्टेयर भूमि पर चावल-परती-परती फसल पैटर्न अपनाते थे। एक्सटेंशन एजेंट से संपर्क, मोबाइल का नियमित उपयोग, तथा आर्थिक व नवाचार प्रेरणा में अधिकांश किसान मध्यम स्तर पर थे। KMAS की उपयोगिता पर प्रभाव डालने वाले कारकों में एक्सटेंशन संपर्क, मास मीडिया उपयोग, संदेश की समयबद्धता और समझ शामिल थे। प्रमुख बाधा तकनीकी शब्दावली की कठिनाई रही, और किसानों ने सुझाव दिया कि संदेश स्थानीय भाषा में भेजे जाएँ।
4. n (PMFBY) का मूल्यांकन से पता चला कि फसल बीमा (PMFBY) लेने वाले किसानों की शिक्षा, भूमि होल्डिंग, परिवार का आकार, आय और फसल उत्पादकता, बिना बीमा वाले किसानों की तुलना में अधिक थी। बीमित किसानों को चुनी हुई फसलों से अधिक कमाई मिली और उनकी कृषि आय प्रति हेक्टेयर भी ज्यादा रही, जिससे स्पष्ट होता है कि फसल बीमा योजना खेती की आय बढ़ाने में सहायक है। योजना सभी किसानों के लिए उपलब्ध है, प्रीमियम पर भारी सरकारी सब्सिडी है, और अब पूरी बीमित राशि का दावा बिना किसी कटौती के मिलता है। छत्तीसगढ़ और रायपुर दोनों में PMFBY के तहत बीमित राशि और क्लेम अमाउंट में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, हालांकि बीमित किसानों और क्षेत्रफल में कुछ कमी आई। तकनीक के उपयोग, रिमोट सेंसिंग और मोबाइल डेटा से दावों के भुगतान में तेजी आई है। कुल मिलाकर, बीमित किसानों की उत्पादन लागत थोड़ी अधिक होने के बावजूद उनकी उत्पादकता, लाभ और क्लेम प्राप्ति अधिक रही, जो योजना की सकारात्मक प्रभावशीलता को दर्शाता है।
5. करीमुल्ला, के. एट अल, (2017) ने अपना अध्ययन भारत में कृषि स्थिरता पर एक विश्लेषण किया इन कृषि योजनाओं से जुड़ी कुछ ऐसी विशेषताएँ हैं जो इन्हें विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण बनाती हैं। कृषि की स्थिरता के इन आयामों की विविधता एवं गतिशीलता को समझने के लिए राज्य-स्तरीय विश्लेषण का उपयोग किया गया। यह अध्ययन 2001 से 2011 के बीच की दो समय-अवधियों के लिए स्थिरता सूचकांक के आकलन पर आधारित था तथा इसमें मानव विकास सूचकांक का प्रयोग किया
6. डे, कुशांकुर और मैत्रा, देबाशीष, (2017) ने भारत में कृषि बीमा: वादा, नुकसान और रास्ते की ओर पर अपना अध्ययन किया। में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) तथा मौसम आधारित फसल बीमा योजना (डब्ल्यूबीसीआईएस) के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया है। यह मूल्यांकन विशेष रूप से खरीफ 2016 तथा खरीफ 2007 से खरीफ 2014 की अवधि के दौरान किया गया है। अध्ययन में विभिन्न प्रदर्शन संकेतकों का उपयोग किया गया, जिनमें प्रति बीमित फसल क्षेत्र औसत बीमित राशि, कवर किए गए ऋणी एवं गैर-ऋणी किसानों का प्रतिशत, प्रति किसान औसत बीमित क्षेत्र, दावा अनुपात तथा बीमित राशि के प्रतिशत के रूप में

प्रीमियम आदि प्रमुख हैं। इन संकेतकों के माध्यम से कृषि बीमा योजनाओं की प्रभावशीलता और व्यावहारिक परिणामों का विश्लेषण किया गया है।

7. Panda (2009). “विकेंद्रीकरण, स्थानीय स्व-शासन और लिंग: अधिक समानता की ओर बढ़ना” विकेन्द्रीकृत शासन और विकास T. M. Joseph (2009) द्वारा संपादित , ग्रामीण विकास, स्थानीय स्वशासन तथा सरकारी योजनाओं के सामाजिक-आर्थिक प्रभावों को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण सैद्धांतिक आधार प्रदान करती है। पुस्तक में यह प्रतिपादित किया गया है कि विकेंद्रीकरण और पंचायत राज संस्थाओं के सशक्तिकरण से ग्रामीण समाज में विकास योजनाओं की पहुँच और प्रभावशीलता बढ़ती है।

2. अध्ययन के उद्देश्य

1. पिछले दस वर्षों में लागू कृषि योजनाओं का अध्ययन करना।
2. कृषि योजनाओं के आर्थिक प्रभावों का विश्लेषण करना।
3. किसानों की सामाजिक स्थिति में आए परिवर्तनों का अध्ययन करना।
4. योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं की पहचान करना।
5. सुधारात्मक सुझाव प्रस्तुत करना।

3. शोध-पद्धति

- यह अध्ययन वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक प्रकृति का है।
- प्राथमिक स्रोत : कृषकों से साक्षात्कार, प्रश्नावली
- द्वितीयक स्रोत : सरकारी रिपोर्टें, जनगणना आँकड़े, शोध-पत्र
- अध्ययन क्षेत्र : छत्तीसगढ़ के चयनित ग्रामीण क्षेत्र
- नमूना चयन : उद्देश्यपूर्ण एवं स्तरीकृत नमूना विधि

4. छत्तीसगढ़ में प्रमुख कृषि योजनाएँ (पिछले 10 वर्ष)

1. न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं धान खरीदी योजना
2. किसान क्रेडिट कार्ड योजना
3. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
4. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
5. मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना
6. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण आधारित योजनाएँ
7. राज्य स्तरीय किसान कल्याण योजनाएँ

आर्थिक प्रभाव

(1) खेती हेतु समय पर और आसान क्रेडिट

छत्तीसगढ़ में 2025 खरीफ सत्र में लगभग ₹5,751 करोड़ कृषि लोन KCC के तहत किसानों को वितरित किए गए, जिससे खेती के शुरुआती खर्च जैसे बीज, खाद, उर्वरक इत्यादि के लिए तत्काल धन मिला। India CSR इससे किसानों को महंगे निजी ऋण (जैसे साहूकार से) पर निर्भरता कम करने में मदद मिली, और खेती की लागत प्रबंधित करने में आसानी हुई। India CSR

(2) उत्पादन लागत और लाभ

शोध से पता चला कि KCC से लाभान्वित किसानों की लागत थोड़ी अधिक हो सकती है, पर नेट लाभ और लागत-लाभ अनुपात (profit/cost ratio) बेहतर मिलता है, जो कृषि गतिविधियों की लाभप्रदता को बढ़ाता है। Extension Journal

(3) ब्याज सहायता एवं सब्सिडी

केंद्र सरकार की Modified Interest Subvention Scheme (MISS) के तहत रियायती ब्याज दर और समय पर भुगतान पर अतिरिक्त सुविधा मिल रही है – इससे ऋण का प्रभावी ब्याज दर कम होता है। The Economic Times

(4) संस्थागत ऋण पर निर्भरता बढ़ी

पूरी भारत में KCC के कारण संस्थागत वित्त (बैंक ऋण) का इस्तेमाल बढ़ा और गैर-संस्थागत उधार की निर्भरता घट रही है, जिससे आर्थिक रूप से किसान समर्थ हुए हैं। DD News

(5) सीधा आर्थिक सहायता प्रदान

कृषक उन्नति योजना के तहत राज्य सरकार ने करीब 24.7 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में लगभग ₹13,320 करोड़ की राशि सीधे हस्तान्तरित की। इसे किसानों द्वारा बेचे गए धान के MSP के अलावा अंतर राशि के रूप में दिया गया। <https://mpcg.ndtv.in/+1>

इससे किसानों की नकदी प्रवाह (cash flow) में सुधार हुआ और वे उत्पादन खर्चों जैसे बीज, खाद, किसानों को आवश्यक तकनीक लेने में सक्षम हुए।

(6) उच्च MSP और बोनस से आय में वृद्धि

कृषक उन्नति योजना के तहत MSP पर धान बेचने पर किसानों को मूल्य अंतर (जैसे ₹917/ क्विंटल अतिरिक्त) के रूप में भुगतान हुआ, जिससे कुल मुआवजा अधिक हुआ और खेती से होने वाली आमदनी वाह्य बाजार दरों की तुलना में बेहतर हुई। India TV News

(7) फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन

कृषक उन्नति योजना की सीमा विस्तृत होने से अब सिर्फ धान ही नहीं, बल्कि मक्का, दलहन, तिलहन जैसी फसलों को भी सहायता मिल सकती है, जिससे किसान फसल विविधीकरण कर सकते हैं और बाजार जोखिम में कमी ला सकते हैं।

Krishak Jagat (कृषक जगत)+1

(8) महंगाई और कर्ज पर सकारात्मक प्रभाव

कृषि लागत के लिए मिली प्रत्यक्ष सहायता से किसान महंगे साहूकार या उच्च-ब्याज ऋण से कम प्रभावित होते हैं, जिससे कर्ज का बोझ घटने में मदद मिलती है।

(9) आय में वृद्धि और लागत में कमी

- जैविक खेती अपनाने से किसानों को रसायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों पर खर्च कम करना पड़ता है, जिस से खेती की लागत कम होती है।
- कुछ क्षेत्रों में सरकार जैविक खेती के लिए प्रोत्साहन राशि (जैसे प्रति एकड़ अनुदान) भी देती है, जिससे किसानों की कुल आय में वृद्धि होती है। Bhaskar

(10) बाजार अवसर और अतिरिक्त आय स्रोत

- जैविक उत्पादों के बाजार में तेजी से मांग बढ़ रही है, जिससे किसानों को उच्च मूल्य मिल सकता है और आय के नए अवसर खुलते हैं।
- उदाहरण के तौर पर ग्रामीण महिलाएं जैविक सब्जियाँ उगा कर बाजार में बेचने या छोटे व्यवसाय (उदाहरण: पशुपालन, डेरी) से “लखपति दीदी” जैसी पहचान बना रही हैं, जिससे उनकी व्यक्तिगत आय भी बेहतर हुई है। Krishak Jagat (कृषक जगत)

(11) स्थानीय रोजगार और उद्यम

- जैविक खेती से जुड़ी गतिविधियाँ जैसे जैविक खाद उत्पादन, प्राकृतिक कीटनाशक बनाना, विपणन आदि ग्रामीण स्तर पर रोजगार उत्पन्न कर रहे हैं, जिससे अर्थव्यवस्था में स्थानीय रूप से वृद्धि हो रही है।
- कुछ प्रगतिशील किसान न केवल खुद जैविक खाद बनाकर लागत बचा रहे हैं, बल्कि तकनीक साझा करके दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। Bhaskar

(12) सीधे मुआवजा भुगतान से आय सुरक्षित

- छत्तीसगढ़ के 1.41 लाख से ज्यादा किसानों को ₹152.84 करोड़ की फसल बीमा राशि सीधे उनके बैंक खातों में भुगतान की गयी। इस राशि ने प्राकृतिक आपदा या फसल क्षति के नुकसान की भरपाई करने में मदद की। IBC24 News
- इससे किसानों के पास आपदा के बाद नकदी (liquidity) बनी रहती है, जिससे वे अगली सत्र की खेती जारी रख सकते हैं और आपका निवेश रोक नहीं पाता।

(13) बीमा फ़ायदे से जोखिम प्रबंधन

- PMFBY से किसानों को प्राकृतिक जोखिमों से होने वाले नुकसान में वित्तीय सहायता मिलती है, जिससे खेती का जोखिम कम होता है और वे कर्ज या साहूकारों पर निर्भरता कम करते हैं। IBC24 News
- समय-समय पर पॉलिसी में किए बदलाव (जैसे क्लेम पॉलिसी और डिजिटल क्रियान्वयन) से किसानों को अधिक भरोसेमंद सेवा मिल रही है। <https://mpcg.ndtv.in/>

(14) स्थिर आर्थिक बुनियाद

- किसानों को फसल नुकसान का भरपाई मिलने से स्थिर नकदी प्रवाह (cash flow) बना रहता है, जो खेती के लिए आवश्यक इनपुट खर्चों, मजदूरी और उन्नत तकनीकी निवेश में सहायक होता है।
- यह कुल कृषि आय को अस्थिर मौसम पर निर्भर रहने से थोड़ा स्थिर बनाता है और आर्थिक जोखिम को कम करता है।

(15) आय में सीधी वृद्धि

- PM-Kisan के तहत हर योग्य किसान को सालाना ₹6,000 मिलते हैं – यह रकम खेती के शुरुआती खर्च जैसे बीज, खाद, उर्वरक, मजदूरी आदि में सीधे उपयोग की जा सकती है। Drishti IAS छत्तीसगढ़ के किसानों ने बताया है कि इससे उधार लेने की आवश्यकता कम हुई, और खेती का निवेश आसान हुआ है। NDTV

(16) कृषि संचालन में मदद

- किसानों ने राशी को बुवाई, खेत जोतने और तकनीकी इनपुट्स पर खर्च कर खेती के उत्पादन को बेहतर बनाया है – जिससे कृषि गतिविधियों का संचालन अधिक सुचारु हुआ है। NDTV

(17) नकदी प्रवाह में स्थिरता

- छोटे और सीमांत किसानों के लिए नकद सहायता का समय पर मिलना लिक्विडिटी (नकदी प्रवाह) में बेहतरता लाता है। इससे कृषि-उत्पादन और घर-परिवार के खर्चों को संतुलित करने में मदद मिलती है। Drishti IAS

(18) सीमित राशि और खर्च की चुनौती

- योजनात्मक सहायता राशि ₹6,000 सालाना औसत-केन्द्रित है और कुछ कृषि-उपयोगों के मुकाबले कम भी लग सकती है। अन्य विशेषज्ञ कहते हैं कि यह राशि खेती की पूरी लागत को कवर नहीं करती, लेकिन एक अतिरिक्त आर्थिक सहायता के रूप में महत्वपूर्ण होती है। Compass by Rau's IAS

सामाजिक प्रभाव

(1) ग्रामीण सुदृढ़ता

- KCC के कारण ग्रामीण समुदायों में आर्थिक स्थिरता बढ़ी है क्योंकि किसान समय पर खेती के लिये फंड प्राप्त करते हैं, जिससे सामाजिक तनाव कम होता है और आत्म-निर्भरता आती है। India CSR

(2) मानसिक एवं सामाजिक सुरक्षा

- समय पर क्रेडिट मिलने से वित्तीय दबाव कम होता है, जिससे किसान परिवारों में तनाव, कर्ज-सम्बंधी विवाद और मनोवैज्ञानिक दबाव घटता है। स्थिर आय और समय पर समर्थन से सामाजिक सुरक्षा में सुधार होता है। India CSR

(3) साक्षरता और जागरूकता

- हालांकि लाभकारी पहल है, पर कई किसानों को KCC की प्रक्रिया और फायदे की जानकारी कम है। एक शोध में लगभग 60% से अधिक किसानों ने योजना के लाभों के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं होने की बात कही, जिससे सामाजिक स्तर पर योजना का पूरा लाभ नहीं पहुंच पाया। [Extension Journal](#)

(4) आत्म-सम्मान और वित्तीय सुरक्षा

- प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के ज़रिए बड़ी रकम सीधे किसानों के बैंक खातों में जाने से उन्हें आर्थिक सुरक्षा और आत्म-सम्मान मिलता है। विकेंद्रीकृत भुगतान से भरोसा मजबूत होता है और सामाजिक तनाव में कमी आती है।

(5) ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार

- आय वृद्धि के कारण किसानों के घरों में भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ता है, जिससे ग्राम्य क्षेत्रों के जीवन स्तर में सुधार देखने को मिलता है।

(6) संघठन और सामुदायिक सशक्तिकरण

- जैसे-जैसे योजना अधिक फसलों तक विस्तारित होती है, किसान समुदायों में सामूहिक निर्णय क्षमता और कृषि संबंधी संगठनों की भूमिका बढ़ती है।
- इससे खेती के फैसलों में किसान अधिक सशक्त और आत्मनिर्भर बनते हैं।

(7) महिलाओं और कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण

- जैविक खेती मिशन के तहत महिला किसान समूहों और महिला स्वयं सहायता समूहों को कृषि गतिविधियों में शामिल किया जा रहा है।
- इससे महिलाओं की सामाजिक पहचान और आर्थिक स्वतंत्रता दोनों में वृद्धि हुई है, और वे परिवार में निर्णय-प्रक्रिया में अधिक सक्रिय हुई हैं। [Krishak Jagat \(कृषक जगत\)](#)

(8) ग्रामीण समुदायों में आत्मनिर्भरता

- जैविक खेती को अपनाने से ग्रामीण किसान रसायन-निर्भर खेती से आज़ाद होकर स्थिर और स्वावलंबी खेती की ओर बढ़ रहे हैं।
- जैसे गाँव को आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से महिलाएँ नियमित आय अर्जित कर रही हैं और कुल मिलाकर सामाजिक आत्म-गौरव और स्थिरता बढ़ रही है। [Amar Ujala](#)

(9) जागरूकता और तकनीकी सीख

- जैविक खेती अपनाने के लिए प्रशिक्षण वर्ग, किसान मेलों, कृषि विभाग के सहयोग से किसानों में तकनीकी जानकारी और कृषि ज्ञान बढ़ा है।
- इससे गाँवों में कृषि साक्षरता बढ़ी, तथा किसान अधिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने लगे हैं। [Krishikosh](#)

(10) गरीब और सीमांत किसानों की मदद

- PM-Kisan विशेष रूप से छोटे/सीमांत और मध्यम किसानों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इस योजना से इन किसान परिवारों को आर्थिक सुरक्षा मिलती है और वे खेती-बाड़ी से जुड़े रहने में आत्म-विश्वास महसूस करते हैं। [IMPRI India](#)

(11) ग्रामीण घरों की जीवन गुणवत्ता में सुधार

- किसानों ने बताया कि PM-Kisan राशि घरेलू खर्चों, बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य और त्योहारों पर खर्च में भी इस्तेमाल होती है – जिससे परिवारों की सामाजिक स्थिति में सकारात्मक प्रभाव दिखता है। [IANS News](#)

(12) कर्जदारी में कमी

- कई किसानों ने कहा कि योजना से उन्हें साहूकारों या महंगे ब्याज वाले उधार से बचने में मदद मिली है, जिससे कर्ज का दबाव कम हुआ है। [NDTV](#)

(13) सामाजिक समावेशन में चुनौतियाँ

- कुछ किसानों, खासकर दूरदराज़ इलाकों में रहने वाले या डिजिटल रूप से अप्रशिक्षित लोगों को योजना-सेवा पंजीकरण में कठिनाई आई है, जिससे उन्हें हर किस्त नियमित रूप से न मिल पाना या योजनाओं की जानकारी का अभाव हो सकता है। [IMPRI India](#)

राज्य-विशेष आँकड़े (छत्तीसगढ़)

- 19वीं किस्त में ~25.95 लाख किसानों को लाभ मिला, राशि लगभग ₹599.38 करोड़। [Amar Ujala](#)
20वीं किस्त में ~25.46 लाख किसानों को लगभग ₹567.77 करोड़ सीधे बैंक खाते में प्राप्त हुए।
[KrishakJagat\(कृषकजगत\)](#)
प्रचारित रिपोर्ट के अनुसार किसानों ने हितार्थ हस्तांतरण का उपयोग खेती-संबंधी खर्च तथा पारिवारिक आवश्यकताओं में किया। [IANS News](#)

(14) सामाजिक सुरक्षा और मनोवैज्ञानिक स्थिरता

- असमय प्राकृतिक घटनाओं (जैसे बाढ़, सूखा) के परिणामस्वरूप फसल खराब होने पर जब किसानों को बीमा के ज़रिए मुआवजा मिलता है, यह उन्हें सामाजिक और आर्थिक स्तर पर सुरक्षा का भरोसा देता है।

तालिका क्रमांक 2 : छत्तीसगढ़ – कृषि योजनाओं का सामाजिक & आर्थिक प्रभाव (2015–2025)

वर्ष	मुख्य योजना / बदलाव	आर्थिक प्रभाव (₹ / लाभ)	सामाजिक प्रभाव
2015–18	पारंपरिक कृषि बजट	औसत MSP पर खरीदी; सीमांत बजट वृद्धि	कृषि आय स्थिर; सीमांत निवेश
2019–20	Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana शुरू	किसानों को लक्ष्य ₹6,000–10,000/acre सहायता	छोटे और सीमांत किसानों को राहत
2020	Rajiv Gandhi Kisan Nyay (आधिकारिक लॉन्च)	>19–23 लाख किसानों को लाभ; ₹5,700+ करोड़ तक आबंटन	सीधा नकद लाभ; खरीद-आधारित समर्थन
2020	Godhan Nyay Yojana शुरू	गौवंश उत्पादों पर मूल्य (₹2/kg)	ग्रामीण रोजगार और ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा
2021–22	कृषि व सहायक योजनाओं का विस्तार	~₹7,000+ करोड़ वितरण	फसल विविधीकरण, खाद, सिंचाई सहायता
2022–23	कृषि बजट अंतर	कृषि क्षेत्र के लिए ₹9,272 करोड़	सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क में वृद्धि
2023	Rajiv Gandhi Kisan Nyay बड़े पैमाने पर लाभार्थी	~24+ लाख किसान	ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नकदी प्रवाह पुनर्जीवित
2023	Input subsidy बड़े पैमाने पर	₹21,900+ करोड़ तक भुगतान	खेती ऑर्गेनिक/तकनीक उन्नयन में सहायता
2024	Krishak Unnati Yojana (केंद्र/राज्य)	₹10,000 करोड़ आवंटन बजट	24+ लाख से अधिक किसानों को समर्थन

वर्ष	मुख्य योजना / बदलाव	आर्थिक प्रभाव (₹ / लाभ)	सामाजिक प्रभाव
2025	कृषि बजट वृद्धि	₹10,000 करोड़ (Krishak Unnati) + अन्य	सस्ता बिजली, बुनियादी ढांचे के निवेश
2025-26	फसल बीमा और तकनीकी समर्थन (PMFBY)	₹150+ करोड़ + डिजिटल भुगतान	जोखिम कम; किसान आत्मविश्वास ↑

7. समस्याएँ एवं चुनौतियाँ / नकारात्मक प्रभाव

(1) दस्तावेज़ी बाधाएँ

कई किसानों को बैंक प्रक्रियाओं के कागजी कार्य, भूमि दस्तावेज़ नहीं होने की वजह से KCC नहीं मिल पाता, जिससे सामाजिक-आर्थिक विभाजन बना रहता है। Extension Journal

(2) डिजिटल और त्रुटियाँ

डिजिटल समस्याओं और बैंक कार्यवाही में देरी से किसानों को ऋण मिलने में बाधा आती है, जिससे आर्थिक लाभ कम हो रहा है। Extension Journal

(3) धोखाधड़ी के जोखिम

देश भर में कुछ मामलों में KCC संग्रहण या ऋण के गलत उपयोग से धोखाधड़ी भी रिपोर्ट हुई है—जैसे कुछ राज्यों में फ्रॉड की घटनाएँ सामने आई हैं, जिससे सामाजिक विश्वास पर असर पड़ सकता है। <https://mpcg.ndtv.in/>

(4) लाभार्थी चयन और पहचान

• कुछ किसान, खासकर सीमांत या भूमिहीन किसान, योजना की पात्रता या पंजीकरण प्रक्रियाओं को समझने में कठिनाई का सामना कर सकते हैं, जिससे सहायता का लाभ समान रूप से नहीं पहुँच पाता।

(5) सूचना एवं पहुँच की कमी

• डिजिटल रजिस्ट्रेशन, बैंकिंग और पोर्टल प्रक्रियाओं को समझना छोटे किसानों के लिए कठिन हो सकता है, जिससे कुछ लाभार्थियों को योजना का पूरा लाभ नहीं मिल पाता।

(6) लाभ राशि उतनी स्थिर नहीं

• योजना मौजूदा समर्थन मूल्य पर आधारित है, लेकिन बाजार की वास्तविक कीमतों की अस्थिरता के कारण किसानों को अभी भी ज्यादा लाभ के लिए अतिरिक्त मार्केट इंटरवेंशन की आवश्यकता हो सकती है।

(7) अभिगम्यता में असमानता

- सभी किसानों तक जैविक खेती की जानकारी या तकनीक समान रूप से नहीं पहुँच पा रही है। खासकर आदिवासी और सामाजिक-आर्थिक रूप से कमजोर क्षेत्रों में जागरूकता और प्रशिक्षण कम होने के कारण जैविक खेती का पूरा लाभ नहीं मिल रहा है। [Krishikosh](#)

(8) बाजार और विपणन अवसंरचना की कमी

- जैविक उपज के लिए विशिष्ट विपणन चैनल, ब्रांड और समर्थन मूल्य की अस्थिरता से किसानों को अपेक्षित मूल्य नहीं मिल पाता है।
- बाजार में प्रामाणिक जैविक उत्पादों की पहचान और प्रमाणन की कमी भी बिक्री को चुनौती देती है। [Down To Earth](#)

(9) संकट के उदाहरण

- कुछ मामलों में जैविक कीटनाशकों में मिलावट या नकली उत्पादों जैसे जोखिम भी सामने आए हैं, जो किसानों और उपभोक्ताओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। <https://mpcg.ndtv.in/>

(10) बीमा पंजीकरण में जागरूकता की कमी

- कुछ इलाकों में पूरी तरह से किसानों तक जागरूकता नहीं पहुँचने के कारण वे योजना का लाभ नहीं ले पाते हैं, खासकर सीमांत और छोटे किसानों में।

6. निष्कर्ष

अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि पिछले दस वर्षों में कृषि योजनाओं ने छत्तीसगढ़ के किसानों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यद्यपि कुछ संरचनात्मक समस्याएँ अभी भी बनी हुई हैं, फिर भी योजनाओं के समुचित क्रियान्वयन एवं निगरानी से किसानों का समग्र विकास संभव है।

7. सुधारात्मक सुझाव

तालिका क्रमांक : 3 समस्याओं के सुधारात्मक सुझाव

क्रमांक	समस्या	विवरण / कारण	सुधारात्मक सुझाव
1	फंड का समय पर न मिलने की समस्या	योजनाओं के लिए बजट आवंटन या निधि वितरण में देरी	बजट प्रक्रिया को तेज करना, डिजिटल भुगतान प्रणाली लागू करना
2	किसानों को योजनाओं की जानकारी का अभाव	जागरूकता अभियान की कमी, सूचना का सही चैनल न होना	मोबाइल/एसएमएस आधारित सूचना प्रणाली, ग्राम स्तर पर प्रशिक्षण शिविर
3	तकनीकी सहायता की कमी	आधुनिक कृषि तकनीक, बीज और उपकरणों की उपलब्धता कम	कृषि extension सेवाओं को मजबूत करना, स्थानीय कृषि केंद्र स्थापित करना
4	भ्रष्टाचार / लाभार्थियों का चयन में अनियमितता	अधिकारी स्तर पर मनमानी, लाभार्थी सूची में त्रुटियाँ	पारदर्शी चयन प्रक्रिया, ऑनलाइन पोर्टल पर लाभार्थियों की सूची
5	सिंचाई सुविधाओं का अभाव	जल संरक्षण की योजनाओं का पर्याप्त क्रियान्वयन न होना	जल प्रबंधन परियोजनाओं को प्राथमिकता देना, ड्रिप/स्प्रिंकलर जैसी सिंचाई तकनीक का प्रोत्साहन
6	बीज और उर्वरक की गुणवत्ता में कमी	नकली बीज और उर्वरक की बिक्री	सरकारी बीज/उर्वरक दुकानों का विस्तार, गुणवत्ता नियंत्रण कड़ाई से लागू करना
7	विपणन और मूल्य निर्धारण की समस्या	किसानों को उपज का उचित मूल्य न मिलना, मंडियों तक पहुँच की कमी	एफपीएम (Farmers Produce Market) और ऑनलाइन मार्केटप्लेस को बढ़ावा देना
8	ऋण और बीमा की समस्या	कृषि ऋण की पहुँच कठिन, बीमा दावे लंबित	सस्ती ऋण और बीमा योजनाओं का प्रचार, त्वरित दावा प्रणाली
9	प्रशिक्षण और कौशल विकास का अभाव	किसानों को नई तकनीक और कृषि प्रबंधन की जानकारी नहीं	नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम, कृषि विश्वविद्यालयों और NGOs का सहयोग
10	मौसम और प्राकृतिक आपदाओं का जोखिम	सूखा, बाढ़, कीट संक्रमण आदि	जलवायु अनुकूल खेती, फसल बीमा, आपदा प्रबंधन योजना का क्रियान्वयन

संदर्भ सूची

- छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विभाग - वार्षिक रिपोर्ट, 2024-2025.
- Panda, Uttam Kumar (2019). Gendering Decision Making and Status Dynamics of Women: A Study of Two-Working Families of India. AJANTA, Vol. 8, No.1, pp. 94-100.

3. Tupat, A. R. and Mahapatra, M. (2019). Social media vis-à-vis Social Networking Sites and Their Impacts on Students. *Ajanta (An International Multidisciplinary Quarterly Research Journal)*, Vol. VIII, No. I, PP. 101-106.
4. कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। (2019). प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। Pib.gov.in. <https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1946816>
5. कुमार, आर. (2020). छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) का प्रभाव। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़, 54-58.
6. यादव, पी. के. (2020). छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में केवीके द्वारा किसान मोबाइल सलाहकार सेवाओं के माध्यम से कृषि में आईसीटी पहल पर एक अध्ययन।
7. के, एस., मलिक, डी. पी., और मलिक, जे. एस. (2022). भारत में KCC स्कीम की प्रोग्रेस का असेसमेंट। *इंडियन जर्नल ऑफ़ एक्सटेंशन एजुकेशन*, 58(3), 33–37. <https://doi.org/10.48165/ijee.2022.58307>
8. Panda, Uttam Kumar & Archana R. Tupat (2023). Social Networking and Cultural Impacts: Insights from Indian University Students. *Educational Administration: Theory and Practice*, 29(4), 3955–3959. DOI: <https://doi.org/10.53555/kuey.v29i4.8715>
9. प्रसाद, डी. (2018). छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में चावल उत्पादकों के बीच संतुष्टि के संदर्भ में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) का मूल्यांकन। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़, भारत।
10. Panda, Uttam Kumar (2009). Decentralization, Local Self-Governance and Gender: Moving towards More Equality in *Decentralized Governance and Development*, Edited by T. M. Joseph, Deep & Deep Publications Pvt. Ltd., New Delhi. ISBN 9781-8450-155-1, pp 50-66.